कि इस संबंध में सरकार को जल्दी ही कोई निर्णय लेना चाहिए और वर्तमान चुनाव आयोग, जिसने खुद यह स्वीकार किया है कि जो मल्टी बाडी इलेक्शन कमीशन है, इस के संबंध में सारी चीजों पर विचार करना चाहिए । इसके साथ ही हमारा यह भी सुझाव था कि जो इलेक्शन कमीशन है, इनकी नियुक्ति की जो शर्तें हैं, उसमें जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारी है उसकी परिधि से बाहर रखना चाहिए । इसके संबंध में सुझाव आए हैं, जिन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है । लेकिन मुझे पूरी आशा है कि इस संबंध में सरकार विचार करेगी । एक माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की कि अगर इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हाथ होगा तो फिर मुकदमें या इलेक्शन पिटीशन जजों के सामने जाएंगे । तो हमें ख्याल पड़ता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उनका इलेक्शन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाता है । जहां तक मैं समझता हूं, मेरी बात की पुष्टि भारद्वाज जी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन जब वे राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाते हैं तो उनका इलेक्शन पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में ही चलता है और ऐसे जज उनको सुनते हैं जो उनके द्वारा ही नियुक्त हों । मैं उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा हूं लेकिन यह वास्तविकता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि मेरे संशोधन को आप स्वीकार करें ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदया, मैंने पहले ही अर्ज किया था कि चाहे मालवीय जी हों या हमारे पक्ष के सदस्य हों, सब ने यह कहा है कि इलेक्शन पर जो कानून हैं उनमें संशोधन होने चाहिएं, रिफार्म होने चाहिएं, लेकिन हर एक की दृष्टि उसके लिए अलग अलग है । जो लोकदल की दृष्टि है वह अलग है, बी० जे० पी० की अलग है, सी० पी० एम० की अलग है, डी० एम० के० और ए० डी० एम० के० की अलग है । किन्तु उनके जो सजेशन्स हैं उनको हम आपस में मिल बैठकर तय कर सकते हैं, उन पर विचार कर सकते हैं । जहां तक बेसिक कमिटमेंट है वह तो आपका और हम सब लोगों का यही है कि इनमें रिफार्म लायें, इससे ज्यादा बार-बार कहने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : महोदया, चूंकि सरकार की ओर से मंत्री जी ने आश्वासन दिया है और मुझे पूरा भरोसा है, यकीन है कि जल्दी इस आश्वासन की पूर्ति होगी । देश के हित में, लोकतंत्र के हित में और देश में स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाओं के हित में आप इस कानून में संशोधन करेंगे, इसी अपने विश्वास के साथ मैं आपकी अनुमति से अपना विधेयक वापस लेता हूं ।

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT BILL, 1985.

(TO AMEND ARTICLE 311)

DR. BAPU KALDATE (Maharastra): Madam, Deputy Chairman, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

उपसभापति महोदया, मैं संविधान में संशोधन करने के लिए अपना विधेयक पेश करता हूं । इस विधेयक को अगर स्वीकार नहीं किया जाएगा तो देश में जो मजदूरों का आन्दोलन है, जिसके सशक्त बनने की प्रक्रिया चल रही है उसको क्षति पहुंचेगी और इसका मुझे बहुत खतरा लग रहा है ।

महोदया, इस संशोधन विधेयक की तरफ आने से पहले मैं कुछ बुनियादी बातें लोकतंत्र के बारे में कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोट का 11 जुलाई, 1986 का जो फैसला है, वह लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जा रहा है । जहां तक हम पढ़े हैं लोकतंत्र को वहां तक हमको यह बारबार सिखाया गया कि—

There are four basic tenets of democracy. There are two 'from' and two 'of'. One is freedom from want and the other is freedom from fear. The third is freedom of expression and the fourth is freedom of worship.

[Dr. Bapu Kaldate]

इसमें दो फोम हैं और दो ऑफ हैं ये कई हो सकते हैं, इनकी सूची बड़ी हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये चार हैं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो को क्षति पहुंचाने वाला है। आप कहते हैं कि प्रजातन्त्र के लिए जरूरी है कि देश की जनता निर्भय हो। . . .

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : निर्भय होकर चोरी करें ? . . . **(व्यवधान)**

डा० बापू कालदाते : निर्भय होकर चोरी करे तो उसके लिए आपके पास बहुत कानून हैं, इसमें आप मत फंसाइए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनसे चोरी करवाएंगे, हम चाहते हैं कि सत्ता का डंडा लेकर आप किसी को जेल में बंद न करें। उसको हम डैमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : हाजी मस्तान हो जाएं ? . . . **(व्यवधान)**।

डा० बापू कालदाते : वैसे मैं इसमें नहीं जाना चाहता था। पहले शुरू करते ही ये जरा डर रहे हैं। जो ज्यादा डरे होते हैं वे ज्यादा हरकते करते हैं। मैं तो कुछ सिम्पल प्रपोजिशन्स लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मैं यह मानता हूं कि देश में लोग निर्भय बनें। यह जो अमेंडमेंट 42 है यह कब आया अगर आपको पता है तो शायद यह इमेरजेंसी में आया हुआ अमेंडमेंट है। There was a case of Chellapan in 1975. And this is my information, I may be wrong, but what I have read is that the Forty-second Amendment was passed in 1976. लेकिन मैंने इसको पढ़ा नहीं है। अगर उस समय आया है, मैं समझता हूं उसी समय आया है लेकिन अगर नहीं आया है तो मैं इसको छोड़ देता हूं। अमेंडमेंट में यह है कि लोगों को लगातार यह डर रहता है कि सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारी कभी भी किसी को निकाल सकते हैं। इसमें 2 (ए, बी, सी) जो प्रोविजन है इसमें से 'बी' और 'सी' बहुत खतरनाक है। 'ए' के बारे में बाद में बताऊंगा। मुझे लगता है इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है। आप लोगों ने भी सारे देश में इसका असर देखा होगा। आप इस को समझिये। 11 तारीख को फैसला हो गया। मैं आप को बयान देकर बताऊंगा जिसमें सिर्फ अपोजिशन के लोग नहीं हैं जिसमें मजदूरों के साथ काम करने वाले एक सक्षम, एक निर्भय मजदूर कार्यकर्ता ललित माकन जैसे कार्यकर्ता हैं। जो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं और एक अति निर्भय मजदूर नेता की हैसियत से उन्होंने काम किया है। यह सदन जानता है और हम भी जानते हैं। जहां-जहां लड़ाइयां चलती रहीं, जहां-जहां मजदूरों के संघर्ष होते रहे उनमें बड़ी निर्भयता से, उन्होंने अपने पक्ष के बारे में, कभी-कभी लोकसभा में भी कहा। यह हम सब लोग जानते हैं। मैं इसको इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि इस पर प्रतिक्रिया हुई है। 11 तारीख को फैसला हुआ, मेजोरिटी फैसला हुआ मैं इसके बारे में आगे कहूंगा। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र रही, खासतौर से मजदूरों के अन्दर तीव्र रही। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। जो यहां के मजदूर आन्दोलन हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, अखबारों ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उन में से कुछ पढ़ कर अवश्य आपको सुनाना चाहता हूं। पहले तो ललित जी की प्रतिक्रिया आपके सामने रखना चाहता हूं :

Lalitji has said on 16th July, 1985: The judgement had put the 12 million Government employees in jeopardy. Who will determine as to whether the disposal is in the public interest? Employees will have to depend on the mercy of the bureaucrats.

यह मैं नहीं कह रहा हूं । यह ट्रेड यूनियन के सक्षम नेता कह रहे हैं । अगर यह 311 का फैसला मान लिया जाय, 311(2) में कोई तबदीली न की जाय, इसमें कोई तरमीम न की जाये, इसमें कुछ बदला नहीं जाये तो all the employees will be at the mercy of the bureaucrats. क्योंकि 'बी' और 'सी' लागू हुए हैं जिसके कारण इसका बाजू निकाल दिया गया है । 311(.1) जो है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है that all the employees, not a small section, as he has rightly said 2 milion employees, will be affected by this. दूसरी जो आल इंडिया एसोसिएशन है उसकी प्रतिक्रिया भी बताना चाहता हूं This is what the All-India Trade Union Congress has said:

"The latest judgment of Supreme Court had upset its own previous full bench judgment regarding article 311(2)(b) of the Constitution. As such, it was a retrograde step giving full powers to the bureaucracy that had 'already earned notoriety' for its resort to victimisation and termination of Union activities.

And this is very important. It further says:

"The judgment, had knocked out the basic principle of natural justice that no one could be punished without being heard and allowed to defend. Thus it amounted to a mockery of fundamental rights."

The Government Employees' National Confederation has said:

"The verdict snatched the fundamental right of a government employee to get an opportunity to explain his case under article 311(2)(b) of the Constitution before dismissal or removal for any alleged offence. The Confederation said the decision could again strengthen the hands of bureaucracy and political authority in the democratics set up of the country."

यह बात तो इन लोगों ने कही है । श्री भाटिया जी यहां पर बैठे हुए हैं । वे कानून की बात करेंगे । वे कानून के विद्वान हैं, मुझ से ज्यादा विद्वान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं आपका ध्यान श्री कृष्णा अय्यर जो जज रह चुके हैं, उन्होंने जो कुछ कहा उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है :

"Justice Krishna Iyer described the recent Supreme Court judgement on dismissal of government servants as retrograde and dangerous. He said that it was an example of class bias of the judiciary. The judgment, though well written and readable, was a negation of the spirit of the Constitution and was violative of the Fundamental Rights under Articles 14, 19 and 21. The judgment imperilled the security of service of the civil servants. There were only two remedies to correct the situation—first, amending the Constitution, and second, referring the matter to Full Bench of the Supreme Court. The Supreme Court arrived at the decision it did because of too much reliance on dictionary."

This is the point. The Supreme Court relied too much on the dictionary.

"We were not governed by dictionary but by the Constitution."

इस फैसले की तरफ हिन्दुस्तान में जो भी ट्रेड यूनियन संगठन हैं, जो भी इम्प्लाइज हैं, उनका ध्यान गया है और वे सब के सब इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गये हैं । मेरा ख्याल है कि बहुत कम मौके एसे आए हैं, जब सब लोग एक हुए हों । दाम बढ़ने के खिलाफ, पे-स्केल बढ़ाने के लिए, काम के घंटे कम करने के लिए और अन्य फैसिलिटीज दिलाने के लिए मजदूर संगठनों ने

[डा० बापू कालदाते]

हड़तालें की हैं, सत्याग्रह किया है, लेकिन यही एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हिन्दुस्तान की सारी ट्रेड यूनियनों ने 26 फरवरी को इस देश में वन डे स्ट्राइक की । यह एक ऐसा मुद्दा था जो अन इकोनोमिक था, यह कोई आर्थिक सवाल नहीं था । मजदूर लोग ज्यादा पेमेंट या ज्यादा सहूलियतों की मांग नहीं कर रहे हैं । इसमें एक बैसिक सवाल था, फ्री फ्राम फीयर, भय से मुक्ति का स्वाल है...(**व्यवधान**) । अगर कोई गैर-कानूनी काम करे तो आप उसको सजा दीजिए । भय से मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप गैर-कानूनी या गलत काम कीजिए । मगर कोई काम नहीं करता है तो आप उसको सजा दीजिए । मेरी समझ में नहीं आता कि भय से मुक्ति का अर्थ यह क्यों लगाया जाता है कि आप जो मर्जी आए, वह कीजिए । लेकिन हमारा यह कहना जरूरी है कि अगर आप किसी को सजा देते हैं तो उसको सुनने का मौका भी दीजिए । कई बार यह देखने में आता है कि जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे कानूनों का गलत फायदा उठा लेते हैं । इमरजेंसी में क्या हुआ, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है । उस समय की प्रधान मंत्री ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने लोग गिरफ्तार कर लिये गये हैं, हमने उनको गिरफ्तार करने के लिए नहीं कहा था । मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की, हमको भी दो साल जेल में रहना पड़ा । हमने सिर्फ महात्मा गांधी का नाम लिया था । क्या महात्मा गांधी का नाम लेना चोरी करना है ? हमने कोई गुनाह नहीं किया था । आप जो भी कानून तैयार करते हैं उसमें यह देखना चाहिए कि गुनाहगार को तो सजा मिले, लेकिन एक भी बेगुनाहगार को सजा नहीं मिले । कोई गुनाहगार सजा पाने से भले ही छूट जाय, लेकिन किसी एक भी बेगुनाहगार को सजा नहीं मिलनी चाहिए । इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्मचारियों में जो घबड़ाहट पैदा हुई है उसके उचित कारण हैं । उन लोगों को भय है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग न हो जाय । इस दुरुपयोग के कारण इस देश में जिस सक्षम ढंग से ट्रेड यूनियनें चलनी चाहिएं वे नहीं चल सकती हैं ।

क्या आप नहीं जानते हैं कि जब कभी स्ट्राइक्स होती हैं, मजदूरों की तब सबसे पहले यह काम होता है कि वहां जो एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको निकाल दिया जाता है, किसी न किसी बहाने निकाल दिया जाता है और फिर उन पर डिसिप्लिन की कार्रवाही चलती रहती है । 1974 में रेलवे की स्ट्राइक हुई । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब स्ट्राइक हुई, तो श्वेत-पत्र निकाला गया, उस रेलवे स्ट्राइक के खिलाफ, उसको कुचलने के लिये आप ने सारी कानूनी व्यवस्था कर दी और लाखों मजदूरों को नौकरी से हटा दिया गया कि घर जाइये । जनता पार्टी का राज आने पर ही उनको रीएस्टेबिलिश्ड किया गया उनको वापिस किया गया । जो उन लोगों को आपने निकाल दिया तो उनको यह अधिकार नहीं था, Freedom of organisation is also a fundamental right. संगठन करने का हमारा अधिकार है, जिससे हमको कोई वंचित नहीं कर सकता । मेरे ऊपर अगर अन्याय होता है, तो मेरा फर्ज बन जाता है कि उसका मुकाबला करूं । कोई भी गरीब आदमी अकेले इन अन्याय का मुकाबला नहीं कर सकता । जो धनी लोग हैं, वे पैसे का बोझ डालकर उस अन्याय को दुरुस्त कर सकते हैं । लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनके पास एक ही शक्ति है, संगठन शक्ति । यह संगठन शक्ति अपोजिशन वालों की ट्रेड यूनियनों में है । कांग्रेस की ओर से भी ट्रेड यूनियनें चलायी जाती हैं । इंटक जिसको आप कहते हैं, इसको आप ही चलाते हैं । यह भी हो सकता है कि वहां के अधिकारियों को अगर लगे कि इंटक एक मजबूत संगठन है और वे अपने संगठन के बल पर जोरदार संघर्ष कर रहे हैं, तो इस धारा 311(2) के तहत उनको भी निकाला जा सकता है । इसमें जो लिखा है, उसको मैं पढ़कर बताना चाहता हूं ।

यह बड़ा अजीब है। इसमें है अगर अथारिटी राइटिंग में उनका एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकती हैं, तो बगैर पूछे उनको निकाल सकते हैं। For some reasons. Who is going to decide the reasons? "Some reasons" means at the mercy of the bureaucrat. He can come and say, 'No, I cannot take the evidence in writing.' " यह हो नहीं सकता, बड़ा लम्बा है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस में 311 (2) (बी) में है कि निकाल दो। जब निकाल दिया तो उसके लिये कोई चारा नहीं है। Remove, dismiss, whatever you can do. इतनी पावर किसी भी सरकार और ब्यूरोकेट के हाथ कभी भी नहीं रहने देना चाहिये। अगर आपको लोकतन्त्र को दुरुस्त रखना है, तो इतनी दण्ड शक्ति अगर आप किसी के हाथ में देते हैं तो यह मत भूलियेगा कि Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. इतनी शक्ति अगर आप उनको प्रदान करते हैं, तो इसमें उनके करप्ट होने की संभावना है। अगर आप उनको अबसोल्यूट पावर देते हैं, तो इससे एबसोल्यूट करप्ट होने का खतरा है। इसलिये मुझे लगता है कि इसमें जो आपने अधिकारियों को उनको निकालने की पावर दे दी है, वगैर इजाजत के, वगैर पूछे बिना सुनवाई के, बिना नेचुरल जस्टिस दिये हुए, यह उचित नहीं है। जो भी प्रावधान 311 (2) (ए) (बी) (सी) में है, इस प्रावधान को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमको नहीं लगता था कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसलिये चुप बठे थे, क्योंकि अभी तक जो भी फैसले निकले हैं, उनमें किसी ने भी इस प्रावधान का आश्रय नहीं लिया और इस तरह की दमन शक्ति की जो प्रक्रिया है, वह मजदूर संगठनों में अभी तक नहीं आई थी, लेकिन इस फैसले के बाद सब मजदूर संगठनों पर इसका प्रभाव होगा। मैं इसको सियासी ढंग नहीं देता। एक बुनियादी लोकतान्त्रिक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं जानता हूं कि लोकतन्त्र में कई खामियां होती हैं, मैं यह भी जानता हूं कि लोकतन्त्रीय प्रक्रिया धीमी होती है, मैं यह भी जानता हूं कि लोकतन्त्र में कुछ गुनहगार शायद छूट सकते हैं। लेकिन जिसकी बुनियाद पर निष्ठा हो, उसकी सारी खामियां देखते हुए भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये, जिसके कारण लोक शाही को मानने वाले या उसकी व्यवस्था को मानने वाले किसी भी व्यक्ति पर उसका हमला हो। इसलिये मैं बहुत गम्भीरता के साथ सदन का आह्वान करने के लिये यह विधेयक लाया हूं। इस विधेयक के जरिये मैं इस बात को आपके सामने लाया हूं जो कि आप को देखनी चाहिये। अब थे जो इसके रीजन्स हैं उस पर जाता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रीजन्स में जाता हूं। यह फैसला, आप जानते हैं, भाटिया जी जरूर जानते होंगे और भी बहुत से लोग जानते हैं कि तुलसी राम पटेल के मामले पर जो कार्यवाही चली उसके कारण यह चीजें सही मायने में निकली। तुलसी राम पटेल एक परमानेंट आडिटर था रीजनल आडिट आफिस, एम०ई०एस० जबलपुर के कार्यालय में इन्होंने एक गुनाह किया और इस गुनाह के कारण इनको सजा हो गई। इनको जो सजा हुई वह आई० पी०सी० की धारा 332 के तहत हुई। वहां के कट्रोलर जनरल आफ डिफेंस जो डिसिप्लीनेरी अथार्टी थी उसने उसको डिसमिस किया और इस सजा को ले कर इस में 311 का हवाला है। 311 (ए) (बी) (सी) में से 311 (ए) का हवाला है उसके तहत इनको निकाला गया है। अब वह हाई कोर्ट में चले गये। उससे पहले 1975 में मिस्टर चलप्पन का एक केस आ गया। इस केस में उसको डिसमिस कर दिया गया जिसमें यह फैसला दिया गया कि उनको सुने बगैर डिसमिस करना ठीक नहीं है। यह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला है। तुलसी राम पटेल को सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्ज, 1965 की धारा 19 की क्लाज 1 में कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया। अब रिटायरमेंट मिलने के बाद वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गये। वह हाई कोर्ट

(डा० बापू कालदाते)

में आर्टिकल 226-227 आफ दी कांस्टीट्यूशन के तहत गये। ऐसे कई मसले अन्य हाई कोर्टस में भी पड़े थे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस नतीजे पर आया कि

What did that High Court held? The High Court held that no opportunity had been given to the respondent before imposing the penalty of compulsory retirement, and on the basis of Chellappan's case the order is defective. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला किया चलप्पन के केस को ध्यान में रखते हुए जो आर्डर कंट्रोलर जनरल ने दिया है वह आर्डर डिफेक्टिव हैं, दुरुस्त नहीं हैं अब यह भी केस आ गया तो यह सारे केसेज मिल कर के पांच जजों की कांस्टीट-यूशन बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट में चले गये। यह बहुत दिनों तक चला। इस बेंच में भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री चन्द्रचूड, जस्टिस ठक्कर, जस्टिस तुलजापुरकर, जस्टिस मदन तथा जस्टिस पाठक थे। पांच पांच जजों की बेंच के सामने यह केस आया तो उन्होंने यह मेजोरिटी डिसीजन लिया कि जो कार्यवाही कंप्लसरी रिटायरमेंट की की गई वह उचित है लेकिन उस में जस्टिस ठक्कर ने डिस्सेंटिंग नोट लगाया। मैं दोनों आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहता हूं, इन्होंने भी वही आर्ग्युमेंट किया है, इनके ग्राउंडज क्या हैं, किन बुनियादी बातों पर उन्होंने यह फैसला किया, यह मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उन्होंने मिजोरिटी डिसीजन में यह कहा है। The main argument in Chellappan's case, I will give you:

> "This principle of natural justice having been expressly excluded by the Constitutional provision, namely, the second proviso to clause 2 of article 311, there is no scope for reintroducing it by side door to provide once again the same enquiry which the Constitutional provision has expressly prohibited."

उनका एक ही बेसिक अरेंजमेंट रहा कि हम क्या करें। 311(2) में एक्सप्रेसली यह कहा है provided that this will not apply. यह एप्लाई ही नहीं करता है और उसमें यह आ जाता है क्योंकि 311(1) के मुताबिक जो भी कुछ एक्सप्रेसली नहीं आ सकता है, 311(1) में जो नहीं आ रहा है और 311(2) के ए० वी० सी० में आते हैं तो हम क्या करें इसमें जो प्रिंसीपुल आफ नेचुरल जस्टिस की बात है जो सही है, होनी चाहिए It is already excluded by the clause itself. तो हमारी मांग तो इसके लिए है जो क्लाज नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड करता है किसी कारणवश हो, वह क्लाज हमको नहीं चाहिए किसी कारणवश जो नैसर्गिक न्याय की प्रक्रिया है। ऐसे लेटिन वार्डस हैं जो मेरी समझ में नहीं आते हैं लेकिन हियरिंग द अदर साइड जिसको एक सादी अंग्रेजी में कहा जाये कि दूसरों को सुनने का मौका चाहिए तो बहुत ही कुछ गड़बड़ है आप ही कहेंगे जब आप जवाब देंगे। नेचुरल जस्टिस कैसे हो सकता है जब वह एक्सक्लूड कर दें 311 से, 1975 में आपने 21वां एक्सक्लूड किया था यही आरग्यूमेंट कहा था श्री सेन साहब ने when the emergency is there. 21 is out. So, 21 was out and we were in jail. अगर आपका मर्डर भी किया जाये तो भी आपको कोई अलग रास्ता नहीं है, यही आरग्यूमेंट हुआ उस समय। अच्छा हुआ कि हमको आपने मारा नहीं, हो सकता है मार भी देते तो हमारे पास रास्ता नहीं होता because it was an emergency. इमरजेंसी में मार सकते थे, जेल में भेज सकते थे जो कुछ करना चाहते थे इसी के कारण उस समय हमने झगड़ा किया था। इसी के कारण कहा था। No Government has any power in the name of democracy. You form your separate dictatorial Government. I have no objection for that. Then we will fight. That is a different matter. But if you say you are a democratic Government, then your government should not use this sort

of power, where the principle of natural justice is excluded on this or that ground.

हमारी तो यह मांग जरूर रहेगी कि इस बात को आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा भी उन्होंने कहा :

The second proviso is based on public policy and is in public interest and for public good and the Constitution makers, who inserted this in Article 311(2) were the best persons to decide where such an exclusionary provision should be there in the Constitution in which this proviso should apply.

तो उनका कहना यह रहा कि भाई जो कांस्टीट्यूशन असेम्बली के विद्वान लोग बैठे थे उन्होंने अपनी बुद्धिमता के मुताबिक उनको जो देश की इंटरेस्ट में बात सूझी उसके मुताबिक उन्होंने यह प्रावजन डाला। इसमें रखना है या निकाल देना है तो they are the best judges.

तो हमसे उनका कहना यह है कि हम हैं, ये संसद् सदस्य हैं, ये राज्य सभा के सदस्य हैं, ये लोग इसके बारे में फैसला करें क्योंकि आप ही लोगों ने फैसला किया, उसके मताबिक हम लोगों ने जजमेंट किया तो आप करिये इसके लिए मैं आया हूं राज्य सभा के सामने कि हम लोग इसके बारे में एक दफा फिर से सोचें और अपनी विजडम इस तरफ लगायें कि लोकतंत्र को क्षति पहुंचाने की कोई भी चीज हमारे संविधान में न हो। यह अगर हम चाहते हैं तो इसके लिए मैं सारे सदन से आग्रह करता हूं प्रार्थना करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर यह कहता है कि हमारी विजडम के ऊपर सारा निर्भर है तो हम सब लोग अपनी बुद्धिमता से और हमारे जो सामाजिक कमिटमेंट हैं, जो बाध्यताएं हैं तथा समाज के साथ जो जुड़े हुए हैं उनके मन में जो कुछ भी आकांक्षा हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर हम खड़े हुए हैं तो इसके बारे में सोचें। अगर आज लाखों मजदूरों के मन में भय पैदा होगा कि ब्यूरोक्रेसी की मर्सी पर उनकी मेहरबानी पर कृपा पर हमको चलना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि इस डर को दुरुस्त करना लोकतंत्र के लिए ही नहीं उसके लिए तो आवश्यक है ही लेकिन एक सक्षम व्यवस्थित सुचारू रूप से चलने वाली जो मजदूरों की शक्ति है उनकी बारगेनिंग पावर को भी हम मजबूत बना सकेंगे और उनके मन से भय निकालकर उनको इस देश की प्रगति की विकास की जो भी सारी प्रक्रिया है ... उसमें उन का सहयोग ज्यादा मिलने के लिए यह आवश्यक है, ऐसा मैं खुद मानता हूं। जैसी उन्होंने माइनारटी जजमेंट दी है ठक्कर साहब ने, इस ठक्कर साहब के जजमेंट में उन्होंने फिर से एक दफा वही दोहराया है।... (**व्यवधान**) तो इसके लिए न्यायपालिका ने यह कह दिया है कि क्या करें, 311(बी) और (2)(बी) तथा (सी) में यह लिखा है कि उसमें नेचुरल जस्टिस एक्सक्लूड कर दिया है, तो हम क्या करें? ऐसे लिखा है। उन्होंने यह भी हम लोगों से कहा है कि आपने ही संविधान पारित किया है, आप ही उसको दुरुस्त कर सकते हैं।

इसीलिए तो आपके पास आया हूं कल्पनाथ राय जी कि यह जो उन्होंने कहा है, उसका हवाला लेकर मैं राज्य सभा में आया हूं कि हमीं लोग उसको दुरुस्त करें, ताकि न्यायपालिका को इस ढंग की आवश्यकता न महसूस हो जाए।

Therefore, I am here.

उन्होंने जो कहा है, ठक्कर साहब ने उसमें लिखा है—

—"And there is no compulsion to overrule it—even if the other point of view were to appear to be more 'attractive' it is neither a good nor a sufficient ground to overrule Challappan."

शब्द भी उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया कि लगने में बहुत आकर्षक लगता है —

—"After all what does Challappan do? It does no more than enjoin in the context of Rule 14(1)(a) and therefor, as a logical corollary, also in the context of Rule 14(1) (b) of the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968, that an emplo-

[डा० बापू क बदाते]

yee must at least be heard on the question of quantum of punishment before he is dismissed or removed from service without holding an inquiry. The ratio of the decision is so innocuous that there is hardly any need to overturn it."

उनका तो कहना यह रहा कि कोई आवश्कता नहीं थी ऐसे ढंग की आपको देने की,क्यों कि जो चलप्पन केस में फैसला किया, एक दफा कम से कम उनको सुनो, इसको ओवररूल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसमें उनका कहना रहा है।

अब दो-तीन बाते, अन्य चीजें हैं जो इससे निकल आ सकती हैं, मैं उनकी तरफ सिर्फ आपका ध्यान खीचूंगा और फिर अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं दो-तीन बातें इसलिये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग इस राय के हैं कि देश की अर्थ-व्यवस्था का पिवट केन्द्र बिंदू, परिवर्तन की आवश्यकता जिसमें हो, यह केन्द्र बिंदू सार्वजनिक उपक्रम हो — सारे भाषणों में आपने भी कहा, आपकी तरफ से भी कई कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी बड़ा जोरदार समर्थन करके कहा कि इस देश में सार्वजनिक उपक्रमों को ऐसे प्रतिष्ठित करना चाहिये—

—That should be the lever of the whole process of change in this country.

कि सारे परिवर्तन की प्रक्रिया यह केन्द्र बिंदू बने और उसके आधार पर देश की परिवर्तन की प्रक्रिया समता की ओर चलती रहे।

इसका एक दूसरा भी अर्थ होता है कि देश धीरे-धीरे अब तो बढ़ ही रहा है, ऐसा आप भी कह रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि बढ़ेगा ही। कोई चाहे नहीं चाहे, तो भी बढ़ेगा। अगर यह सार्वजनिक उपक्रम बढ़ते जायेंगे तो इस सार्वजनिक उपक्रमों में नये लोगों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ती जायेगी, नये कानून निकलेंगे, नई-नई प्रक्रियायें चलती रहेंगी। तो सरकार और क्वासी, निम्न सरकारी क्षेत्रों में इम्पलायीज की या उनके यहां काम करने वाले लोगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जायेगी और बार-बार ट्रिपार्टाइट कानफ्रेंसेज में हिन्दुस्तान की सरकार से यह कहा गया है कि—

—They are the best employers.

ऐसे कहते हैं। मैं इसके लिये सुझाव ला रहा हूं कि जो आशंका आज ट्रेड यूनियंस और मजदूरों के मन में आई है, उसको अगर यह 311(2) जिसको मैंने कहा कि इसको ओमिट कीजिये, यह जो 311(2) और (3) है, अगर इसको आप तुरन्त ओमिट करेंगे, तो यह हो सकता है कि आप भी एक अच्छे इम्पलायर हैं। यह जो आप बार-बार ट्रिपार्टाइट कानफ्रेंसेज में कहते हैं, उसको पुष्ट मिलेगी। मैं तो सरकार की इसमें मदद करना चाहता हूं कि सरकार जो बार-बार कहती है कि हम अच्छे से अच्छे इम्पलायर हैं, उसके बारे में जो शंका मजदूरों में आई है, उसको दुरुस्त करने का आपको मौका है। जब कोई पोलिटिकल मामला आता है, तो सरकार बड़ी तेजी से करती है। आप भी जानते हैं कि सी आर०पी० सी० 125 का मामला आ गया शाह बानो केस में और जब आपको लगा कि इसका राजनीतिक असर हो रहा है तो तुरन्त सदन में आकर आपने एक अलग से कानून बनाकर कोई व्यवस्था कर दी मुस्लिम महिलाओं के बारे में और यह कितना अच्छा है तथा कितना बुरा है इस समय इस बहस के लिए समय नहीं है।

When you feel a political necessity, you run, you rush.

परन्तु आप भागकर यहां आ गए और आपने कहा कि इसको बदलना बहुत आवयश्क हैं। ये 20 लाख मजदूर यहा नहीं कि इनकों जब चाहे निकाल दो। यह बढ़ने वाला क्षेत्र है और अगर बढ़ने वाले क्षेत्र में यह भय रहेगा कि उनके जो अधिकारी हैं वे कभी न कभी उनको निकाल सकते हैं तो यह ठीक नहीं। इसके लिए आप जरा समझदारी से काम लें तीव्रता से सोचें कि,

This is the sector which helps the developmental processes in this country.

वहां खामियां हैं, गलतियां हैं लेकिन अलग अलग ढंग की होती हैं। शायद कुछ लोग गुनाह भी कर सकते हैं। क्या हम गुनाह नहीं कर सकते हैं कौन नहीं करता हैं। उन पर आप कुछ रहम करो। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम भी गलतियां करते हैं। हम खुद अपने आपसे पूछें। क्या हम गलतियां नहीं करते हैं? जैसे आप ही बार-बार हमारे नेता पर इलजाम लगाते थे, उसको मैं छोड़ देता हूं। हम लोग भी गलती करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि हमने अगर गलती की तो ऐसा कानून जारी करें जिसमें बगैर गलती करने वाले भी सजा पा सकें। ऐसे कानून हम खुद के लिए क्यों नहीं बना रहे हैं? जो डिवेलपमेंटल एक्टीविटीज में सब से बड़ा हिस्सा लेने वाला मजदूर वर्ग है, जो गवर्नमेंट एम्पलाईज हैं, अलग-अलग प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग हैं उनके मन में यह भय पैदा करेगा और इससे काम नहीं चलेगा। मैं एक बहुत पुराने बुजुर्ग कामगार नेता, मजदूर नेता स्व० श्री एम०एन० जोशी जी का उल्लेख करता हूं, स्वतंत्रता पूर्व काल में जो भी मजदूरों के आन्दोलन हुए और जो भी कुछ उस समय इने-गिने महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे, जिन्होंने मजदूरों के हित के लिए काम किए, उनकी निर्भयता के लिए और उनको एक संगठित शक्ति बनाने के लिए जिन्होंने प्रयास किए उनमें से मैं श्री जोशी जी को मानता हूं। जो सरकारी काम करने वाले मजदूर हैं उनके बारे में उन्होने कुछ बातें जरूर कहीं थीं और एक नैगेटिव बात कही थी। उन्होने कहा था कि सरकार को यह समझना चाहिए कि सरकारी नौकर या सार्वजनिक प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले मजदूर आपके गुलाम नहीं हैं।

It is a contractual and mutual understanding amongst the both.

यह एक कान्ट्रेक्ट है आपस में म्यूच्युअल अंडरस्टेंडिंग है, आपस में समझदारी है। किसके लिए? देश के प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए, देश के विकास की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए। अगर यह 311 का फैसला ऐसे ही जारी रहेगा तो यह बात आप समझ जाइये कि मजदूरों के मन में भय पैदा करने का प्रयास भी ब्यूरोक्रेट्स करेंगे और कहेंगे कि you are my slave.

आप हमारे गुलाम हैं और हम आपके मालिक हैं। वैसे तो आज हालत भी यही है जहां तक आप लोग माननीय सदस्य बैठे हुए है और आप भी दफतरों में फोन करते होंगे। फोन करते-करते आपको भी पता लगता होगा, मैं तो मजाक में कभी कभी फोन करता हूं, हमारा फोन जब कोई उठाता है और हम कहते हैं कि मैम्बर पार्लियामेंट बात कर रहा हूं तो वह कहता है, यस सर, क्या सेवा करें? इसका सही मतलब है कि आपने क्यों फोन किया क्या सेवा करूं, इसका मतलब है कि आप क्यों फोन कर रहे हैं, और आप हमको तंग कर रहे हैं क्योंकि आपके फोन का कोई न कोई जबाब देना पड़ेगा। वे नहीं चाहते और यह होता रहता है कि टालते रहिए। हम प्रेस काउंसिल के मैम्बर बने और यहां के अध्यक्ष महोदय ने हमको मनोनीत किया। आपको आश्चर्य होगा उपसभापति जी कि जो आई एंड बी मिनिस्ट्री है उससे हमको एक महीने तक पता ही नहीं लगा और हमने अखबार में पढ़ा कि कल प्रेस काउंसिल की मीटिंग है। हमने राज्य सभा सचिवालय से पूछना शुरू कर दिया कि आपने कब कागज भेजे, कब नोमीनेशन भेजा? उन्होंने कहा कि हमने तुरन्त भेजा। हमने आई एंड बी में इत्तिला की कि क्या हो गया। पता चला कि नाम स्क्रीनिग के लिए होम मिनिस्ट्री के पास गया। यह मुझे मालूम नहीं था कि जिसको राज्य सभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं उसका नाम भी स्क्रीनिंग के लिए गृह मंत्रालय के पास जाता है। दो मीटिंग होने के बाद फैसला हो गया उसको अमल में लाने के लिए दो महीनें लगे आई एंड बी मिनिस्ट्री की तो यह हालत है। वहां के बैठे हुए जो सब लोग है, बड़े पालिश्ड हैं, अच्छी भाषा बोलते है, लेकिन काम की हद तक कुछ नहीं

[डा० बापू कालदाते]

करते हैं ? अगर हमारे साथ इनका यह व्यवहार होता है तो आप क्या मानते हैं कि उनके साथ काम करने वाले जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनसे कैसा व्यवहार कर सकते होंगे ? हम मानते हैं कि सब कुछ उनके साथ कर सकते होंगे और इसलिए मैं उनके हाथ में शक्ति नहीं देना चाहता हूं, बिल्कुल शक्ति नहीं देना चाहता हूं, जिसके कारण मजदूर मेहनत करने वाला मध्यम क्लास का आदमी या बाबू या लोअर कैडर वाला यह महसूस करे कि वह उनका गुलाम होकर बैठा हुआ है। यह आज उनका मन है और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि उसके मन को समझने का प्रयास हम लोग करें। अब जैसा कृष्णा-अयर साहब ने कहा कि यह डिक्शनरी के मीनिंग से काम नहीं चलते, सामाजिक परिवर्तन जो होते है, वह कानूनी शब्दों से नहीं होते हैं बल्कि जनता की आत्मा की आवाज से होते रहते हैं। वैसे तो कानून अंग्रेजों ने भी बनाए थे, लेकिन चले नहीं क्योंकि आत्मा इस देश की बिगड़ गयी कि हम लड़ेंगे इसके खिलाफ कानून तोड़ देंगे, जो कानून हमारी स्वतंत्रता के मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है और एक दफा नहीं दस दफा गांधी जी ने इन्हें तोड़ा। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे कानूनों को आप हौवा बनाकर रखें कि डिक्शनरी देखिए कि "ए" के मायने क्या होता है या "बी' के मायने क्या होता है । प्रश्न यह है कि ट्रेड यूनियन के संगठनों पर इसका क्या असर होगा। जैसा कि आपने सोचा—शाहबानों के कस में 125 धारा का असर सारे मुस्लिम समाज पर पड़ा, लेकिन जो बिना बोले रहने वाले थे उन पर कोई असर नहीं पड़ा बल्कि जो बोलने वाले थे उन पर बहुत असर हो गया और हल्ला किया गया कि मुस्लिम समाज पर यह अन्याय हो रहा है। हो गया क्या ? सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन तुरन्त आपने उसे बदल दिया। तो क्या हम इन सभी बीस लाख मजदूरों और नए आने वाले मजदूरों के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं ।

महोदया, दूसरी बात यह है कि यह बात भी आप सोच में रखिए कि पब्लिक अण्डरटेकिंग वाले और सरकार जिस रवैये को अख्तियार कर रही है, उससे ज्यादा बिगड़े हुए प्रायवेट सेक्टर वाले है। उनको ज्यादा छूट मत दीजिए। एक बात मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं, अभी चार-पांच दिन पहले यहां एक सवाल आ या था और यह सवाल था कि पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई इलैक्ट्रानिक मशीन बैठा रहे हैं और इस बारे में बार-बार यह सवाल पूछा गया कि इससे कितने लोगों को आप सर्विस से निकाल रहे हैं और बार-बार यही कहा गया कि जितने लोग बैठे है, उनको हम रखने वाले है, लेकिन यह नहीं कहा कि नए लोग लेते है। मैं तो यह कहूंगा कि एक अविवेकपूर्ण यांत्रिकीकरण इस देश में हो रहा है। इनडिस्क्रिमिनेट मैकेनाइजेशन और सोफिस्टिकेशन जो हो रहा है, इसका असर तमाम हमारे देश की बेरोजगारी पर होगा। एफ०सी०आई० के बारे में हमने सुना कि वालण्टरी रिटायरमेंट शुरू हो गया है और थोड़ी संख्या में नहीं बल्कि बहुत लोगों का वालण्टरी रिटायरमेंट कर रहे हैं। तो यह एक हथियार बन जायेगा 311(2) जिसके कारण जिसको नौकरी से निकालना है, उसको निकाल दीजिए। आज भी एम्पलायमेंट में वालण्टरी रिटायरमेंट सर्विस बहुत जगह आयी है, आप यह न सोचिए कि सिर्फ यह एफ०सी०आई० में ऐसा है। एफ०सी०आई० का तो अलग है, अगर मझे सवाल करने का मौका मिलता तो उनसे पूछ लेता। लेकिन यह सिर्फ एफ० सी०आई का नहीं है और भी कई संस्थानों में, प्रतिष्ठान में यह बात चल रही है कि लोग अगर जल्दी घर जाने के लिए तैयार है तो उनको दीजिए क्योंकि आप जो यंत्र ला रहे है उनमें इनकी जरूरत नहीं है। नए लोगों को ले नहीं सकते है क्योंकि बैन है और इसी कारण पिछले दो-तीन साल से किसी को लिया नहीं। हमारी राजभाषा के लिए भी लोग चाहिए, जब लेने की बात आती है तो सरकारी अधिकारी उसी की ओर अंगुली दिखा देते है और ले नहीं रहे हैं। इसलिए में कहता हूं कि एक और हथियार बनेगा यह लोगों को विक्टीमाइज करके लोगों को घर भेंजने का। इसलिए यह अधिकार हम नहीं चाहते कि आप लें ।

महोदया, में कहता हूं कि इसको आप सिर्फ कानूनी तौर पर न लें, कानूनी

कानूनी तौर पर न सोचें, यह भी मत सोचिए कि मैं विरोधी दल की तरफ से आमने सामने इसे पेश कर रहा हूं। इसको मैं एक शुद्ध, एक अधिक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक मानता हूं और इसको स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ भी खामियां हमारे मन में या हमारे दिमाग में आयी होंगी या सूझी होंगी, जो शायद कानून के न समझे हुए मन में आयी होंगी उसको दुरूस्त करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम है और हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे ज्यादा हामी है ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो मैंने संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सिंपल है। इसमें यही कहा गया है कि 311 (2) और 311 (3) तो है उसको हटा दिया जाए 311 (1) को आप उसमें रहने दीजिए। मैं यह चाहता हूं कि इसके लिए इतनी मांग है कि उसको आपको दूरूस्त करना चाहिए। इसलिए उसको आप रिड्राफट करें तो उससे भी यह हो सकता है, ऐसा कानूनी विषेशज्ञों की राय से हो सकता है। अगर वे सुझाव दें कि 311 (2) में यह परिवर्तन करने से हमें जिस ध्येय की तरफ जा रहे हैं वह ध्येय पूर हो सकेगा तो मुझे इसके लिए खुशी होगी। इसलिए मैं आपसे इसमें संशोधन करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि 311 (2) में क्या परिवर्तन लाएं कि जिससे सब लोग, सारे मजदूर इसका स्वागत करें। इस दृष्टि से आप इस संशोधन की तरफ देखिए।

यही कहकर मैं यह संशोधन विधेयक सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं।

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Madan Bhatia.

SHRI MADAN BHATIA (Nominated): Madam Deputy Chairman, Jesus Christ on the Cross had said: "Father, forgive them; they know not what they do." Dr. Bapu Kaldate does not seem to know what he is doing.

SHRI KALPNATH RAI: Right.

SHRI MADAN BHATIA: Madam, I have never come across in my short parliamentary career a Statement of Objects and Reasons of a Bill which is so totally at variance with the contents of the Bill. The speech, of course, runs along the Statement of Objects and Reasons. But, so far as the Bill is concerned, this is not only totally irrelevant, but is also completely contradictory to the Statement of Objects which the honourable Member has moved.

Madam, the Statement says:

"The recent judgment of the Supreme Court on article 311(2) of the Constitution of India upholding the right of the Government to dismiss or remove from service or reduce in rank a civil servant without an inquiry or without giving him a chance of being heard will reduce the status of the civil servants."

This has been the refrain of the speech of the honourable Member that as a result of the existing provisions, namely, article 311(2) and its exposition by the Supreme Court, government servants can be dismissed without any opportunity of being heard. So, the honourable Member has proposed that article 311(2) should be deleted. Now, let us go to clause (2) of article 311 and see what it says. Article 311(2) says:

"No such person..." —namely, the Government servant—" ...as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges."

[The Vice-Chairman (Shri M. P. Kaushik) in the Chair].

Now, Sir, the Bill says that Clause (2) shall be omitted. Are you really serious about omitting clause (2), Mr. Kaldate?

DR. BAPU KALDATE: I am serious and I want redrafting of it. That is what I have said.

श्री कल्पनाथ राय : देखिये मानसिक दिवालियापन... (व्यवधान)

SHRI MADAN BHATIA: You have not said it. Can redrafting be done at this stage?

SHRI KALPNATH RAI: No.

SHRI MADAN BHATIA: I am respectfully submitting, Sir,....

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, this is a Private Member's Bill. Mr. Bhatia, this is a Private Member's Bill. I would like Mr. Bhatia to enlighten us on the legal aspects of the Supreme Court judgment. That is what I want. (*Interruptions*).

SHRI MADAN BHATIA: That is what I am going to do.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Please address the Chair; do not address him.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Let him explain the legal aspects, Sir. (*Interruptions*).

SHRI MADAN BHATIA: I am doing exactly the same thing, Sir.

Sir, the honourable Member says clause (2) shall be omitted. This is what he says in the Bill. In fact, Sir, it is clause (2) alone which is helpful.

DR. BAPU KALDATE: It provides for something more and therefore, there is a contradiction and that is why I want redrafting of it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Mr. Kaldate, why do you speak while sitting?

SHRI MADAN BHATIA: I respectfully submit that it is only clause 2 contained in this Constitution, article 311, by virtue of which a Government servant has been given the constitutional guarantee and protection of hearing before any action is taken against him regarding dismissal, removal or reduction in rank. And if you omit clause 2, if you pass this Bill, that would mean the constitutional protection and the guarantee which has been enshrined in article 311 will stand omitted. And the Government servant will be left totally forlorn so far as the constitutional protection is concerned. I respectfully submit, Sir, that this may be a Private Member's Bill but I should have expected a little more seriousness from the hon. Member in proposing to amend the Constitution before moving this Bill. The Constitution is a sacred document. It was given to us by the founding fathers of India. If you want to amend the Constitution you have to spend days and nights in studying the rationale of any particular provision which you want to be amended. Here is an hon. Member who comes forward with this Bill seeking to amend article 311, without having read article 311.

SHRI KALPNATH RAI: He will apologise.

SHRI MADAN BHATIA: Secondly, the hon. Member says that this provision was introduced in 1975 during the emergency. He also quotes Tulsiram Patel's case. All that I can say, Sir, is that the hon Member has been briefed with regard to a few particular paragraphs from that judgment but has not read the judgment. This provision, article 311(2), as is stands today was introduced by the founding fathers of the Constitution in 1950 when this Constitution was adopted after a long and arduous debates in the Constituent Assembly, and this provision was introduced on the basis of section 241 of the Government of India Act, 1935. The whole provision was lifted and incorporated in the Constitution after a thorough deliberation by the founding fathers

of the Constitution. Article 240 is identical with article 311(2) of the Constitution. (*Interruption*) I will come to (3). So to say that this amendment should be deleted because it was introduced during emergency is nothing but travesty of truth.

Thirdly, Sir, in the Aims and Objects the hon. Member says that the ruling of Supreme Court will definitely stop the flow of efficient and highly qualified persons into public services and they may go to foreign countries. So the assumption is that these Government servants and public servants enjoy greater protection in Britain and the United States, these democracies, than in India. I wish he had spent a little more time in studying Tulsiram Patel's Judgement in the Supreme Court. In that very judgment he would have come across the whole detailed position expounded by the Supreme Court as regards the civil servants in the United Kingdom. In the United Kingdom there is absolutely no constitutional or statutory guarantee so far as Go-

They hold their office at the pleasure of the Crown and they can be dismissed at will. I will draw the attention of this hon. House to the position in Great Britain. In England, except where otherwise provided by statute, all public officers and servants of the Crown hold their appointments at the pleasure of the Crown. When a person holds office during the pleasure of the Crown, his appointment can be terminated at any time without assigning any cause. In 1970, the House of Lords held: "It is now well established in British constitutional theory at any rate, as it has developed since the 18th century, that any appointment as a Crown servant, however subordinate, is terminable at will unless it is expressly otherwise provided by legislation." And the hon. Member thinks that if you take away the protection of Clause (2) of Article 311, they will go to Britain to enjoy greater protection.

4 P.M.

The hon. Member has quoted Challapan's case and said that the Supreme Court has reversed Chillapan's case inasmuch as in this case the Supreme Court said that here was a man whose services were terminated because he was not affored any opportunity of being heard. Now, this is nothing but an example again of ignorance on the part of the hon. Member with regard to Chellapan's case. In Challapan's case, on the other hand, the Supreme Court intervened on the ground that although the inquiry was not held and it might not have been held at all, but the circumstances were such that they did not warrant the dismissal of the Government servant and imposition of a major penalty and it was incumbent upon the disciplinary authority to take into consideration the entire conduct of the Government servant, surrounding circumstances and the nature of the misconduct that he had committed before coming to the conclusion that his services were required to be terminated without any inquiry. It was only by way of passing observation that the Supreme Court held that when a Government servant's service is terminated, he should also be heard. This *obiter dicta* of the Supreme Court in Chellapan's case came up for consideration in Tulsi Ram's case. In Tulsi Ram's case, the whole question was gone into in detail. Tulsi Ram Patel made history in the Supreme Court by taking recourse to proviso to Article 311(2), not to Article 311(2) but to proviso to Clause (2) of Article 311. Tulsi Ram Patel was a permanent Auditor of the Civil Defence Accounts Department of the Government of India posted at Jabbalpur. His increment was stopped for one year by the Controller of Defence Accounts. When he received the orders, he goes into the room of his superior officer. He says "Why has my increment been stopped?" His superior officer replies: "I have no authority to stop your increment." Now, Tulsi Ram Patel

[Shri Madan Bhatia]

whose champion Dr. Kaldate, the hon. Member, has become, took up an iron rod, struck him on the head and threw him down the chair. He started bleeding profusely. The gentleman had to be removed to the hospital. Tulsi Ram Patel whose champion Dr. Kaldate is, was arrested and convicted. When he was convicted, then Clause (a) of the proviso to Article 311(2) was invoked which says that if a Government servant is convicted by a criminal court, then in that case further inquiry shall not be necessary and his services should be terminated. So his services were terminated. Tulsi Ram goes' to the Supreme Court. Supreme Court says, ' if in circumstances such as this a further inquiry is called for before taking any action against Tulsi Ram Patel, then this will be nothing but a travesty of the principles of a natural justice.' And it is for these reasons that the founding-fathers of the Constitution introduced this exception to Clause (2) of article 311 which is in public interest and for public good because a Government servant is not merely a contractual employee but he has a status, he has a responsibility towards the public, that invisible body which is the State of India. He owes a responsibility to the State of India, to the public of this country. And if a Government servant behaves like this and convicted by the court and then he has the audacity to demand a further inquiry before any action is taken against him, this will be reducing the principles of natural justice to utter nonsense...

SHRI KALPNATH RAI: Mockery.

SHRI MADAN BHATIA: Therefore, the Supreme Court upheld this particular interpretation of the proviso to Clause (2) of article 311 which says that no Government servant shall be dismissed without a hearing. But then there is an exception which says: 'Provided further that this clause shall not apply—(a) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge." This is all that the proviso (a) says. And he says that this whole clause should go. If the whole clause goes, then why is he talking about the proviso? Then, Sir, the hon. Member has said, "I will take back this Bill provided this hon. House can point out some alternative safeguards so far as the Government servant is concerned" Now, I respectfully submit again, Sir, that the hon. Member has not read the judgment. The Supreme Court says that there are eight safeguards before the proviso to caluse (2) of article 311 can be invoked. And they are not only sufficient but they are also completely efficacious and are adequate safeguards before any proviso is invoked against a Government servant, namely that no enquiry need be held. What are those safeguards? I have read proviso (a). There are provisos (b) and (c). Proviso (b) says—"Where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank satisfied that for some reason, to be recorded by the authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry." Proviso (c) says "where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry.". The Supreme Court says the first safeguard is that this proviso cannot be invoked unless the disciplinary authority comes to the conclusion that the misconduct is of such a category that it calls for a major punishment, namely dismissal, reduction in rank or removal. And before any such opinion is formed by the disciplinary authority, that disciplinary authority must take into consideration the entire history of his service, his entire conduct, the surrounding circumstances in which this action is sought to be invoked, the nature of the misconduct or the charges against him. And unless and until all these circumstances point to

the taking of a major penalty, none of these provisos can be invoked. This is exactly what happened in Chellapan's case where the disciplinary authority did not apply its mind to these factors. The order of dismissal without inquiry was struck down by the Supreme Court and I will draw your attention to what the Supreme Court said in this regard. This is what they said: "It is obvious that in considering this matter the disciplinary authority will have to take into account the entire conduct of the delinquent employee, the gravity of the misconduct committed by him, the impact which his misconduct is likely to have on the administration and other extenuating circumstances or redeeming features if any present in the case and so on and so forth." And Tulsi Ram Patel's case says so far as Chellapan's case is concerned, it is not possible to find any fault either with the view that neither clause (a) of second proviso to article 311(2) nor clause (1) of rule 14 of the Railway Service Rules, is mandatory or with considerations which have been set out in the judgment and so on. They have not expressed any dissent. They have rather concurred in the judgment of the earlier judgment in Chellapan's case that this is the first safeguard which is imposed upon the disciplinary authority before invoking any of these provisos. Then the second safeguard is that under the service rules the Government servant has got the right of appeal against the order of the disciplinary authority. And before the appellate authority he has got the right in the exercise of his right of appeal to say that the penalty of dismissal or removal is too harsh and should not be imposed upon him. And the appellate authority will go into this representation made in appeal by the Government servant. Number three, the Government servant has got the right to tell the appellate authority that the situation has changed as a result of which it is possible and practicable to hold an inquiry. It is reasonable to hold an inquiry and if the situation has changed the appellate authority is bound to hold an inquiry. Now, in a number of cases it has been stated that post-hearing should be provided instead of prehearing. For instance, when a person's passport is imoounded, the Supreme Court has said that before the impounding of the passport the opportunity of hearing need not be given but after the passport is impounded, the hearing must be given. The Supreme Court says in this case that post hearing is available to the Government servant by way of an appeal or revision. The fourth is that the disciplinary authority cannot dispense with inquiry arbitrarily. The restriction is contained in the Constitution itself. It says: when in the interests of the security of the State it is not expedient to hold an inquiry or when it is reasonably not practicable to hold an inquiry. Now, I give two examples. In my professional career, I came across a case which I dealt with in 60s. In 1965, when Pakistan attacked certain portions of Jammu, there were some employees of the Civil Defence Accounts Organisation of the Government of India who were in position in that area. They ran away. They left their posts and ran away. There was no one to look after that particular department. In those circumstances, the President of India terminated their services on the ground that it is expendient and in the interests of the security of the State that they should be dismissed without inquiry. Will this hon. House say that the President went wrong? Then take the case where it has been said that reasonably it is not practicable to hold an enquiry. In the Tulsi Ram Patel's case, there was one such connected case that came for consideration. Members of the Central Industrial Security Force went on strikes and on agitations, who were looking after the Bokaro Steel Millls. They shifted their activities to Delhi and they started indulging in the same hooligan-

[Shri Madan Bhatia]

ism. Some of them were arrested. They were released on bail. They went back to Bokaro. In Bokaro they created such an atmosphere of violence, intimidation and terror that the Government had to call in the army against the security force. When the army was called in, these members of the Central Industrial Security Force dug in the sand bags and held the armoury, captured the arms, and prepared themselves for fighting against the army. The army announced to them on the loudspeakers and otherwise that please surrender your arms and give up the control of the armoury. What was the result? They started firing back at the army. One Major was killed; three soldiers were killed. There was a pitched battle for a number of hours. Ultimately, the army overpowered them and after that many of them were arrested. Cases were tried against them. When it came to holding enquiry against them for taking action against them for dismissal or removal, they started intimidating and terrorising all the witnesses. Many of them absconded and went underground so that there should be no enquiry against them. In these circumstances, second proviso (b) was invoked against them that it was reasonably not practicable to hold an enquiry against them, and the Supreme Court said, if in circumstances such as these you still call for an enquiry, then you destroy the whole administration. They lost in the Supreme Court. They have found a champion in Dr. Kaldate, and the hon. Member says it has been left to this hon. House to decide whether these clauses should be modified or should not be modified. Supreme Court says: 'We do not express an opinion. Let the Parliament decide whether it is good or it is bad.' Again, the hon. Member has shown total ignorance of this judgment I will draw the attention of this hon. House to the relevant provisions, and what the Supreme Court says about the rationale of these provisions. The Supreme Court says:

> "From the nature of things, the task of efficiently and effectively implementing these policies and enactments, however, rests with the civil services. The public is therefore vitally interested in the efficiency and integrity of such services. Government servants are after all paid from the public exchequer to which everyone contributes either by way of direct or indirect taxes. Those who are paid by the public and are charged with public administration for public good must, therefore, in their turn bring to this charge of duty, a sense of responsibility. The efficiency of public administration does not depend only upon the top echelons of these services; it depends as much upon all the other members of such services even on those in the most subordinate posts. It is, however, as much in public interest and for public good that government servants who are inefficient, dishonest or corrupt or have become a security risk, should not continue in the service and that the protection afforded to them by the Acts and the rules made under article 309 and article 311 be not abused by them to the detriment of public interest and public good."

This is what the Supreme Court said, and the hon. Members says that the Supreme Court has left to this hon. House to decide what is in public interest and what is for public good. Then, Sir, I was dealing with the various safeguards. The third safeguard which I have already pointed out, which the Supreme Court has laid down, is that the disciplinary authority cannot dispense with the enquiry arbitrarily. The Supreme Court says:

> The disciplinary authority is not expected to dispense with a disciplinary enquiry lightly or arbitrarily, or out of ulterior motives or merely in order to avoid holding the enquiry, or, because the depart-

ment's case against the Government servant is weak and must fail.

The hon. Member, Mr. Kalpnath Rai was asking me what clause (e) says. Clause (c) says that the decision of the President or the disciplinary authority under clauses (a) and (b) shall be final. But the Supreme Court says that it may be final at the administrative level; it is not final so far as the courts are concerned. The Supreme Court says:

> The finality given to the decision of the disciplinary authority under article 311(2) is not binding on the court so far as the power of judicial review is concerned. In such a case, the court will strike down the order dispensing with the enquiry as also the order imposing penalty.

Sir, the next safeguard is, the reasons have to be recorded in writing. sub-clause (b) of clause (2) of article 311 says:

> "where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority inwriting, it is not reasonably practicable to hold such enquiry:....

He is not to decide in the mental working of his mind. He has to give cogent, relevant and material reasons and he has to record those reasons, why it is not reasonably practicable to hold an enquiry. The Supreme Court says in its judgement." The reasons must not be vague. The reasons must not be merely a repetition of the provisions contained in article 311(2). The reasons must be detailed reasons. They must be cogent reasons. They must be relevant reasons." Only then, the enquiry can be dispensed with.

Then, the Supreme Court says that although article 311(2) does not say that the reasons should be communicated to the Government servant concerned, they must be communicated for the simple reason that a Government servant who is dismissed without an enquiry has a right to move the court to show that there were no cogent, relevant, reasons for taking action against him, without an enquiry. Those reasons would be justiciable. Therefore, he has a right to have the reasons communicated to him. If the reasons are not communicated to him, he can go to the court. The court shall ask the Government to disclose the reasons and if the reasons are still not disclosed, the court shall presume that there were no good reasons and the order of dismissal will be struck down. So far as sub-clause (c) is concerned, where the enquiry is dispensed with because it is expedient in the interest of the security of the State, the action is to be taken not even by the disciplinary authority, but by the President of India. In a case where the security of the State is involved, action can be taken only by the President of India.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Or by the Governor.

SHRI MADAN BHATIA: Governor in the case of the States. Even the disciplinary authority cannot take action. Of course, the President will be exercising his Constitutional function, namely, on the aid and advice of the Council of Ministers or the Minister or the Secretary concerned under the rules of business. But it will be the highest authority not directly connected with the Government servant who would be taking the decision whether it is expedient in the interest of the security of the State to dispense with the enquiry or not to dispense with the enquiry. These are the inbuilt safeguards in article 311(2) of the Constitution itself. Can we think of any other safeguards? He has a right to go in appeal. He has a right to go to the court. He has a right to have the reasons recorded. He has a right to the com-

[Shri Madan Bhatia]

munications of the reasons. He has a right to show before the appellate authority and before the court that the reasons are arbitrary or they are not relevant or they are *malafide* or that the case of the Government is weak and, therefore, enquiry is not being held against him. And he has a right to move the appellate authority even at the appellate stage to say that although there was an atmosphere of intimidation and terror at the time when the enquiry was to be held by the disciplinary authority, because there was a mass-scale breakdown of discipline as in the case of Central Industrial Security Force, the situation has changed so far as I am concerned, the things have calmed down, it is possible for you to be held an enquiry against me it is possible for you to find witnesses without intimidation and terror, and therefore, at this stage, hold an enquiry against me. And if that is so the appelalte authority is bound to hold an enquiry against him.

Therefore, I respectfully submit that this Bill, which seeks to amend article 311(2), which is against the Statement of Aims and objects of the Bill, ought to be rejected completely because, firstly, this is the only Constitutional safeguard so far as clause (2) is concerned as regards Government servants, and if my hon. Member has made a mistake, he should withdraw this Bill and bring forth an amendment of the provisos. But after what I have submitted before this hon. House, I think and I hope the hon. Member will not do so.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir the mover of the Bill; I think, is confused in his mind relating to the provisions contained in the Constitution of India. The argument that was advanced by my predecessor is quite convincing. The mover of the Bill has not at all applied his mind to the provisions contained in part IV relating to Services under the Union and the State Government. This Chapter, this part, is especially embodied in the body of the Constitution. Provisions of articles 309, 310 and 311 relate to the services of the civil servants, articles 309 and 311 are the safeguards to the civil servants. Provision under article 309 is very convincing which gives ample powers to the Parliament or to the State legislature regarding civil services. I will just draw your attention to the provision in article 309 which says:

> "Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State."

What the recruitment and service conditions should be is left to the Parliament and the State Legislatures. I will go a little further:

> "Provided that it shall be competent for the President or such person as he may direct in the cases of services and posts in connection with the affairs of the Union, and for the Governor of a State or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the State, to make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed to such services and post until provision in that behalf is made by or under an Act...."

Therefore I submit that full scope is given under the Constitution to the legislative bodies and the legislative bodies have, after giving full thought to the conditions prevailing in the country, framed an Act or rules under which the Government servants should work and elaborate provisions have been embodied in the Act and the rules as just explained by my predecessor. There are provisions for giving notices, for giving statements, for making enquiries, for holding en-

quiries, for going in appeals, and even after that the power of review of the judgment is given to them. They are not at all unprotected, as is made out by the Mover of the Bill. I want to draw your attention to the fact that all these provisions are embodied in public interest and for public good. If the civil servants desire to take the law in their own hands, desire to spread disaffection on the assumption that they are unprotected, they are not looked after, it will create chaos. Are the cases uncommon in this counry that there are espionages are the cases uncommon in this country that there is corruption which cannot be proved, are the cases uncommon in this country that today only in the **Indian Express** the paper and confidential records of the President are being disclosed to the public, are not sometimes the most secret records and documents published in the newspapers? If we are going to hold an enquiry on such matters, I think no justice would be given to the public; there would be chaos. Hence considering all these matters, certain provisions are made, looking to the circumstances of each case and with a particular view.

I wish to draw your attention to a very important point. Under Art. 311, if the provisions embodied in the proviso clauses (a), (b) and (c) are attracted in a particular case, then there is no necessity of making any enquiry or holding any enquiry for that purpose. The cases enumerated in clauses (a), (b) and (c) of second proviso are quite clear, because the relationship between the government servant and the government is different. The government servant, as soon as he enters government service, acquires a status that a servant does and his rights and obligations are no longer determined by any contract by both the parties but by statute or statutory rules. All his conduct is controlled by statutes or statutory rules which may be framed or altered unilaterally by the Government. So, these relations are not contractual. But, as soon as they enter into Government service, they become subject to all these Acts, rules and regulations and the Constitution of India. If they want to observe these, they can very well stay. If they do not want to obey them, they are entitled to resign. But they cannot say that these are contractual relations and we will work only on such and such conditions. No, that is not so: Therefore, I submit that the assumption that there are contractual relations is absolutely wrong.

Secondly, Sir, if you look at article 310, what does it say? It says, "Except as expressly provided by the Constitution, every person...." The framers of the Constitution wanted to protect some persons. Therefore, they are not subject to all these articles. It says:

> "Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all-India service or holds any post....."

He is bound by these Acts but certain persons are excluded. Why? They are excluded because they have to deal with very important matters. And who are excluded? The Supreme Court Judges, the High Court Judges, the Auditor-General, officers and members of the Public Service Commissions and the Chief Electoral Officer—because they have to do their own work independently. So it is not a common matter. When these articles were embodied in the Constitution, they were not simply embodied like that. To apply your mind for a change of the constitutional provisions is not as easy as you think.

Sir, I would also like to draw your attention to a third thing. If a situation arises, say, for instance, there is an explosion in the railways, an explosion in the post office or there is explosion of some bridges, and by circumstantial evidence it can be inferred that such and such person or

[Shri Madan Bhatia]

such and such body is involved in it, should not the Government issue certain orders taking into consideration all these provisions? Knowing full well that the Government servants are involved in it, let them not lose any time. If they stand to lose time just making inquiries and calling for the witnesses and giving dates after dates, the whole purpose of these provisions will be defeated.

Sir, Dr. Kaldate referred to both the judgments—the Chellappen Judgment and the Patel Judgement. Really what has happened? Let us see the judgement. I quote:

> "On July 1985, a five-member Constitution Bench of the Supreme Court consisting of Chief Justice Y.V. Chandrachud, Justice M.P. Thakur, Justice D. P. Madom, Justice Tulzuparkar and justice R.S. Pathak by a majority of 4 : 1 (with Justice Thakkur dissenting) partly overruled the judgement in Challappan Case and held that natural justice principles are completely excluded from the purview of the second proviso....."

That is important.

> "....and the punishment under that proviso will have to be imposed *ex parte*. Accordingly the Court allowed the appeals of the Union of India and dismissed the writ petitions and transferred cases of the aggrieved government servants."

This is what it is. It was misquoted. It was wrongly suggested that it was not so. Therefore, I submit, Sir, that this is all confusion that is prevailing in the mind of the mover. (*Time bell rings*).

Just a minute, Sir. I am finishing. I will just draw your attention.

> "Under our Constitution, this is *provided for by the Act and rules* made under article 309 as also by the safeguards in respect of the punishments of dismissal, removal or reduction in rank provided in clauses(1) and (2) of the article 311."

Therefore, it amounts to this, all directions are given by making Acts, by making rules and by the Constitution. If we go a little further, we find,

> "....under article 309 and by article 311 be not abused by them to the detriment of public interest and public good. When a situation as envisaged in one of the three clauses of the second proviso to clause (2) of article 311 arises and the relevant clause is properly applied and the disciplinary inquiry dispensed with, the concerned government servant cannot be heard to complain that he is deprived of his livelihood. The Court expressed the view that the livelihood of an individual is a matter of great concern to him and his family but this is a matter of his private interest and where such livelihood is provided by the public exchequer and the taking away of such livelihood *is in the public interest and* for public good, the former must yield to the latter."

Therefore, I submit, Sir, that the mover is absolutely misconceived in his thoughts and putting the provisions before the House. I oppose the Bill.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र कालदाते जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे यह विधेयक बिल्कुल मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। हमारे देश का संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संविधान बनाया है वह राष्ट्र की सारी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया। संविधान में जो क्लाज 311 है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इनके बिल का क्या उद्देश्य है, वह मैं बताना चाहता हूं।

"The recent judgement of the Supreme Court article 311(2) of

the Constitution of India upholding the right of the Government to dismiss or remove from service or reduce in rank, a civil servant without an inquiry or without giving him a chance of being heard, will reduce in status of the civil servants. The conduct-rules governing the service conditions of Government employees which were framed by the British to keep the Indian bureaucracy under their thumb, are still being continued in varying degrees by successive Govvernments even after 38 years of Independence. The previous Govvernments have put the civil servants at the mercy of the higherups in the hierarchy, leaving little hope for them.

"This ruling of the Supreme Court will definitely stop the flow of efficient and the highly qualified persons into public services and they may go to foreign countries or join the private sector where they are governed by various Labour Laws and principles of natural justice with better perks and service conditions.

"In order to remove this lacuna, deletion of clause (2) and clause (3) of article 311 is sought.

"Hence this Bill."

श्रीमान्, जो बिल यहां पर पेश किया गया है, उसम जो कुछ कहा है उसका आप देखिये । धारा 311 म कहा गया है—

"No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges:

Provided further that, there it is proposed, after much inquiry, to impose upon him any such penalty, such penalty may be imposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry and it shall not be necessary to give such person any opportunity of making representation on the penalty proposed:

Provided further that this clause shall not apply (a) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or (b) where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry; or (c) where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry.

If, in respect of any such person as aforesaid, a question arises whether it is reasonably practicable to hold such inquiry as is referred to in clause (2), the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank shall be final."

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान संविधान सभा के सदस्यों ने बनाया था, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बनाया था। श्री बापू कालदाते जी अपनी बहस के दौरान तीन बातें कहीं। एक बात उन्होंने कही कि निर्भय बनो, दूसरी बात यह कही कि 1974 में रेलवे की जो हड़ताल हुई उसमें रेल कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया और तीसरी बात उन्होंने यह कही कि इमरजेन्सी में जुल्म और ज्यादतिया की गई। ये तीन तर्क उन्होंने प्रस्तुत किये। हमारे देश की भतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चोर-बाजारी करने वालों, तस्करी करने वालों, हत्यारों, राष्ट्रद्रोहियो और राष्ट्रघातियों को जेल में बंद किया तो जनता सरकार सत्ता में आते ही हाजी मस्तान से कहा कि निर्भय रहो, बखियां से कहा कि डरों मत, देश को लूटों, देश हत्याएं करों, मुल्क को बर्बाद

श्री कल्पनाथ राय

करो। यह जनता सरकार की निर्भय की परिभाषा है। सन् 1974 की रेलवे की हड़ताल का जिक्र किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय जो देश के 14 प्रान्तों में सूखा पड़ा हुआ था तो श्रीमती इन्दिरा गांधी सूखा पीड़ित इलाकों में रेलों के माध्यम से अनाज पहुंचाना चाहती थी, पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहती थी तो उस समय श्री जार्ज फर्नेन्डीज ने रेलवे की हड़ताल करवाई और 15 सौ करोड़ रुपयों की मांग की। बंगलादेश जंग के कारण हमारे देश की अर्थ व्यवस्था चकनाचूर हो चुकी थी, ऐसे मौके पर जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की, क्या उनको नव बर्खास्त करना अच्छा काम नहीं था? श्री जार्ज फर्नेन्डीज का यह काम जनघाती और राष्ट्रघाती था।... (**व्यवधान**)। मैं ईल्ड नहीं करता हूं... (**व्यवधान**)।

SHRI K. G. MAHESWARAPPA (Karnataka): I am on a point of order. Can the hon. Member refer to a person who is not in the House. He is talking of George Fernandes, who is not in the House.

श्री कल्पनाथ राय : श्रीमन्, उन्होंने सन् 1974 के रेल हड़ताल का जिक्र किया है। अगर जार्ज फर्नेन्डीज वहां पर मौजद नहीं है तो उन्होंने इसकी चर्चा क्यों की जब 14 प्रान्तों में सूखा पड़ा हुआ था, सरकार वहां पर अनाज की व्यवस्था करना चाहती थी तो ऐसे समय में रेल हड़ताल करना क्या जनघाती और राष्ट्रघाती कदम नहीं था? राष्ट्रघाती और जनघाती कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार सरकार को होना चाहिए। श्री जार्ज फर्नेन्डीज रेल कर्मचारियों के लिए 15 सौ करोड़ रुपयों की मांग कर रहे थे। सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई थी। उस वक्त उन्होंने क्या किया। जार्ज फर्नेन्डीज खुद कैबिनेट मंत्री बने थे। लेकिन जो 15 सौ करोड़ रुपये की मांग 1974 में की गई थी। जब 77 में ...

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: Are we discussing about Mr. George Fernandes? What is this? I strongly object to it.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो 15 सौ करोड़ रुपयों की मांग जो 1974 में रखी गयी थी। 1977 में एक भी पैसा रेलवे के कर्मचारियों को नहीं दिया गया तो क्या यह जनघाती राष्ट्रघाती कदम नहीं था? आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इमरजेंसी को बात बापू कालदाते जी ने की कि इमरजेंसी में बड़ी सख्ती हुई, बड़े राष्ट्रघाती कदम उठाये गये। आदरणीय उपसभाध्यक्ष, मैं पूछना चाहता हूं कि ....

SHRI K. G. MAHESWARAPPA: That is why people have thrown you out—because of emergency.

श्री कल्पनाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण क्रांति के नाम पर उस समय गुजरात विधान सभा के सदस्यों के घरों में आग लगाई जा रही थी, उस समय गुजरात में कांग्रेस सदस्यों के लड़के लड़कियों का अपहरण किया जा रहा था, उस समय समपूर्ण क्रांति के नाम पर पूरे हिन्दुस्तान में फौज को बगावत करने का नारा दे रहे थ। उस समय पुलिस हड़ताल की बात कर रहे थे, उस समय समग्र क्रांति के नाम पर रेल की पटरियां उखाड़ी जा रही थी, समय क्रांति के नाम पर मारकाट, खून खराबा कर बाजार गर्म था, उस समय प्रधानमंत्री के घर पर और राष्ट्रपति भवन पर लोग आमरण अनशन कर रहे थ। और देश के शस्त्रागारों पर कब्जा करने का नारा दे रहे थे मैं, उन्होंने आल इंडिया रेडियों पर कब्जा करने का नारा दिया था, सशस्त्र क्रांति का आवाहन जब उन्होंने किया तभी श्रीमती गांधी के इमरजेंसी लगाई... (**व्यवधान**)... आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय इसलिए बापू काल दाते जी का जो दल है यह मैं बिल्कुल ही गलत कदम उनका मानता हूं। हिन्दूस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिये डिसप्लिन इज नाट नेगोसेबल। हिन्दुस्तान एक विकासशील देश हैं और अगर 25 सौ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की आमदनी है तो हमको 19सौ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों को देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी निर्माण के काम में लगाये जायें, उत्पादन के काम

में लगाये जायें जिससे देश का उत्पादन बढ़े राष्ट्र की दौलत बढ़े और तभी हम आजादी को लड़ाई के हिन्दुस्तान को सामने रखकर भविष्य के सुनहरे दिनों का निर्माण कर सकते हैं। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हाजी मस्तान की हिम्मत यह कहने की हो गई है कि मैं राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लडूंगा। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जब देश के तस्कर, देश में चोर बाजारी करने वाले, राष्ट्र द्रोही, जनघाती और साम्प्रदायिक तत्व इस तरह की बातें करते हैं तो ऐसी ताकतों को कुचल देने के लिये यह जरुरी है कि भारत सरकार सख्त से सख्त कदम उठाये क्योंकि हमारे समाने सबसे बड़ा प्रश्न अपनी आजादी को बचाने का है और देश की आजादी को हम तभी बचा सकते हैं जब हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शक्तियों को बल दें। आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, देश को तोड़ने वाली, जनघाती, और राष्ट्रघाती ताकतें बढ़ रही हैं तथा साथ ही दुनियां की साम्राज्यवादी ताकतें हिन्दुस्तान को डिस्टैबलाइज्ड करना चाहती हैं, ऐसे दौर में डिसिप्लिन इज नाट नेगोसेबल, अनुशासन के लिये कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, इन शब्दों के साथ मैं डा० बापू कालदाते द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): Mr. Chimanbhai Mehta. Not here. Mr. N. K. P. Salve. Not here.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Sir, I want to say a few words.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. KAUSHIK): All right.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Mr. Vice-Chairman, Sir, the argument raised by my hon. friend, Dr Bapu Kaldate is a very simple one. It is with regard to proviso only. I think the whole criticism that can be lodged is this: whole article 311 is one direction and the proviso is in contrast. Therefore, that should be done away with. I think, the vehement appeal that was made by my learned friend may not have been within the framework of the article itself, but it has some bearing.

The founding fathers of the Indian Constitution had very well realised that we have given all protections to the services but there was no duty provided to those services under article 311 and even article 311(2) had very wide repercussions. They thought that it must be restricted to a certain amount of duty and also certain reservations were made with regard to those factors which could be of national importance, which could harm the production, which could restrict the very progress of the country. Therefore, reservation was made in Article 311(2) to take away that wider protection provided in the main Article. Now, the whole question still remains. I do not want to give a number of illustrations to show as to how services are behaving in this country, how the very wide powers that are being provided in Article 311(2) is proving counter-productive so far as production in this country is concerned. That is one ground.

One of my learned friends have just referred to the fact that the concept of natural justice is not applicable to the proviso. Fortunately or unfortunately, when I used to read a case and when there was no point made out, I used to search out whether somehow or the other, the very concept of natural justice can be imparted in or not because it was then guaranteed that for twenty years, we will litigate only on this ground upto the Supreme Court, principle of natural justice can be taken and the whole scope of litigation, the very purpose of the proceedings can be defeated. Therefore, in order to do away with such an exigency, the founding fathers of the Indian Constitution had well contemplated that in those fields of services where we cannot sustain such a liberty, such a

[Shri Bir Bhadra Pratap Singh]

freedom, such a protection to the services in the interest of the country, this proviso was made. I quite agree with the feelings of Dr. Bapu Kaldate that we must grant protection to our services but the state of affairs proving otherwise and the founding fathers of the Indian Constitution were quite correct when they contemplated that the services would not realise their duty when they are dealing with this protection. Nobody can be dismissed in this country before 20 years, I can assure and that is my practical experience. The avenues of litigations are such—civil litigation, thereafter writ jurisdiction, then appellate jurisdiction, then Supreme Court—that there could be no limit to litigation, that has been proved and by chance, if the concept of natural justice was important, then I think, there could be no restriction.

[**Mr. Chairman** in the chair]

The experience has established very well that the founding fathers of the Indian Constitution were very correct when they had provided a proviso in contrast with the main section in the national interest and in the broader interest. Therefore, all this talk that it is a proviso which is anti-labour or the judgment is anti-labour, all this, I think, is not very correct concept. (*Interruptions*). Mr. Chairman, Sir, if you ask, I will sit.

MR. CHAIRMAN: You have got half a minute.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Sir, the hon. Prime Minister is here to make his statement but if I am allowed to continue in the next discussion, I will end up here.

MR. CHAIRMAN: Right.

THE BUDGET (GENERAL), 1987-88—GENERAL DISCUSSION—Contd.

THE PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF FINANCE (SHRI RAJIV GANDHI): Mr. Chairman, Sir, I would like to thank all the Members who have participated in the debate on the Budget. We have received many constructive suggestions and some interesting points from the Members and I would like specially to commend the high level of debate that has taken place in this House.

5. P.M.

Mr. Chairman, Sir, the economy is strong and buoyant, the growth rate has been about 5 per cent, as had been planned in the Plan. The industrial rate of growth has averaged 8 per cent in the last three years, and, as I said in the Budget Speech, this is the highest in twenty years. An important aspect of this industrial growth is that much of it has taken place in the small-scale sector, which means that it is very broad-based and has given employment to a large number of people and it has widened our industrial base. Agriculture has shown a tremendous resilience in spite of drought as many Members are aware; they have always been chasing me about it. In spite of drought for three or four years our food output has not dropped and our food-stocks are full; we have plenty of food. The infrastructure for the third year in succession has averaged an increase of 9 to 10 per cent. This too is a very high figure and a very good performance. Inflation is under control and the trade deficit has been reduced by Rs. 1000 crores. So, the overall picture of the economy is very positive and it shows that we have moved in the right direction. That brings me to one of the points that some Members had made when they question—I remember the word—the direction of the Budget. I would like to remind Members that we do not see the Budget as a sign-post for changing the direction every year. If the country is to progress, we must have a steady course, and the steady course was laid down by Gandhiji before independence and was steered by Panditji and Indiraji post-independence. So, those that see direction in a changes of direction have obviously been disappointed. The direction that we have been given is based on strengthening the nation, based on self-sufficiency, being able to stand up on our own two feet, based on having an independent economy and being strong enough to have